भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2418

जिसका उत्तर मंगलवार, 03 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

फेम इंडिया योजना

2418. श्रीमती किरण खेर:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफेक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (फेम), इंडिया की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और उक्त योजना के अंतर्गत विगत दो वर्षों के दौरान कितने वाहनों की बिक्री की गई है;

(ख) इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कुल कितना बजट आवंटित और जारी किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा चंडीगढ़ सहित देश में सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (ग): जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और वाहन संबंधी उत्सर्जन के मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 2 वर्षों के अवधि के लिए मार्च, 2015 में फेम इंडिया योजना के चरण-I को अनुमोदित किया। योजना के चरण-I को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बढ़ोतरी दिनांक 31 मार्च, 2019 तक थी। फेम इंडिया योजना के चरण-I के दौरान प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर और उद्योग एवं उद्योग संघों सहित सभी स्टेकहोल्डरों से परामर्श करने के बाद, सरकार ने दिनांक 08 मार्च, 2019 को फेम इंडिया के चरण-II को अधिसूचित किया जो ₹10,000 करोड़ की कुल बजटीय सहायता के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आरंभ होकर तीन वर्षों की अवधि के लिए है। यह चरण मुख्यतः सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण की सहायता करने पर केन्द्रीत होगा, और प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों की सहायता करने का लक्ष्य है।यह योजना चंडीगढ़ सहित समूचे भारत के लिए है। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत चार्जिंग अवसंरचना के सृजन की भी सहायता की जाएगी।

योजना के आरंभ होने से अब तक लगभग ₹359 करोड़ के मांग प्रोत्साहन देकर लगभग 2.8 लाख वाहनों की सहायता की गई है और फेम इंडिया योजना के चरण-I के तहत ₹280.00 करोड़ (लगभग) की कुल बजटीय सहायता के साथ 425 ई-बसों की सहायता की गई।

फेम इंडिया योजना के चरण-II के तहत विभिन्न शहरों (नगर परिवहन उपक्रम) को ₹2800 करोड़ (लगभग) के सरकारी प्रोत्साहन से लगभग 5595 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर की गई हैं।

*****